दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

फरवरी (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- राज्य में अब तक धान की खरीदी का आँकड़ा 94.57 लाख मीट्रिक टन के पार 3
- राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय 3
- ग्रामोद्योग मंत्री ने किया हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ 4
- सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के भूमिहीन श्रमिकों ने गांधी 'सेवाग्राम' और छत्तीसगढ़ 'अमर जवान ज्योति' की आधारशिला रखी 5
- छत्तीसगढ़ 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना को लागू करने वाला 35वाँ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बना 5
- 109 वर्षों बाद स्वतंत्रता सेनानी का अंतिम संस्कार 6
- छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 राजपत्र में प्रकाशित 6
- नरवा के उपचार से जल स्तर 1.6 मीटर तक बढ़ा 7
- छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का पिछला रिकॉर्ड टूटा 7
- देश के पहले आईडिया लैब का उद्घाटन 8
- छत्तीसगढ़ के उर्वरक मांग में केंद्र ने की 45 फीसद की कटौती 9
- राज्य में शुरू हुआ 'सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0' 10
- शासकीय विभागों को अब 10 प्रतिशत छूट के साथ मिलेंगे 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के उत्पाद 10
- प्रदेश में कोदो-कुटकी-रागी के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा 11
- छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब 61 लघु वनोपजों की खरीदी 11
- सबके लिये आवास मिशन 12
- अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने की अधिसूचना 12
- 'ओरो स्कॉलर'और 'प्रोजेक्ट इन्क्ल्यूजन' कार्यक्रम शुरू 13
- छत्तीसगढ़ में नौनिहालों के लिये की जाएगी 'बालवाड़ी'की स्थापना 13
- रायपुर और दिल्ली में खुलेगा बस्तर कैफे 14
- राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन 14
- राज्य में चलेगा 'टेबलेट से पहले टॉयलेट अभियान' 15
- कमिश्नर ने किया स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ 15
- छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ज़िले में आत्मानंद हिन्दी स्कूल खोलेगा 16
- तीन नदियों के संगम पर शुरू हुआ 'राजिम माघी पुन्नी मेला' 16
- तालाब गहरीकरण के दौरान प्राप्त हुई योग नरसिंह की विरल प्राचीन मूर्ति 17
- गढ़कलेवा चौपाटी का शुभारंभ 17
- राज्य में 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये शुरू होगी 'बालवाड़ी'योजना 18
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 69.50 लाख राशन कार्ड जारी 18
- छत्तीसगढ़ के आकांक्षी और हाईबर्डन ज़िले में होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण 19
- विशेष प्रोत्साहन पैकेज में अब प्लास्टिक एवं टेक्सटाइल्स उद्योग भी शामिल 19
- ई-पास के ज़रिये अब खाद्यान्न का वितरण 20
- स्कूल शिक्षा विभाग को मिला डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा-2022 अवार्ड 20
- छत्तीसगढ़ के अमनज्योति को मिलेगा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 21
- डी.एन.बी. कोर्स के लिये मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बना दुर्ग ज़िला अस्पताल 21
- मुख्यमंत्री ने तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का किया लोकार्पण 22
- अब छत्तीसगढ़ में कृषि में गोमूत्र का होगा वैज्ञानिक उपयोग 22
- छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग का आईसीसीआर के साथ एमओयू 23
- गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ 23

नोट :

छत्तीसगढ़

राज्य में अब तक धान की खरीदी का आँकड़ा 94.57 लाख मीट्रिक टन के पार

चर्चा में क्यों ?

- 31 जनवरी, 2022 तक छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के चालू सीजन में 94.57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है। पिछले सीजन 2020-21 में आज की स्थिति में 92.803 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी।

प्रनुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि गत वर्ष आज की तिथि तक 20.54 लाख किसानों ने धान बेचा था, वहीं इस वर्ष 21.38 लाख किसानों से धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में अब तक किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 17,906.33 करोड़ रुपए जारी कर दिये गए हैं।
- किसानों की मांग और जरूरत को ध्यान में रखते हुए किसानों की सहूलियत के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की तिथि एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब पंजीकृत किसानों से 7 फरवरी तक धान खरीदी की जाएगी।
- राज्य सरकार ने इस वर्ष 24 लाख से अधिक किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। अब तक मिलर्स द्वारा डीओ और टीओ के माध्यम से 54.99 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।
- छत्तीसगढ़ राज्य ने केंद्रीय पूल में चावल जमा कराने के मामले में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 14.46 लाख मीट्रिक टन केंद्रीय पूल में गुणवत्तापूर्ण चावल जमा करा चुके हैं। इनमें भारतीय खाद्य निगम में 8.03 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 6.42 लाख मीट्रिक टन जमा चावल शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ को इस साल केंद्रीय पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल जमा कराना है।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरूआत 1 दिसंबर, 2021 से हुई है। इस साल धान बेचने के लिये रिकॉर्ड 24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत धान का रकबा भी 30 लाख 15 हजार हेक्टेयर से अधिक है।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 1 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किये जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- राज्य में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत 'जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट' हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में वृहद्, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत 'इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र' हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया।
- 'कौशल्या मातृत्व योजना' के तहत सामाजिक-आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई।

- राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि पाँचवीं अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु उक्त संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, जो कि 31 दिसंबर, 2023 की कालावधि के लिये निरंतर प्रवृत्त रहेगा।
- नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावशील रहेगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिये 'राजीव युवा मितान क्लब योजना' को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बाँस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया।
- 'छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन' तथा 'राजीव युवा मितान क्लब योजना' के वित्तीय पोषण के लिये उपकर राशि लिये जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि भारित होगी।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन यान (एसपीवी) रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संरचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हेतु पूर्व के नियमों में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

ग्रामोद्योग मंत्री ने किया हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 2 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने दुर्ग जिले के विकासखंड धमधा के अंतर्गत ग्राम कोड़िया में हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया और 80 हितग्राहियों को इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस हथकरघा केंद्र में प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में कुल 20 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की समय-सीमा 4 माह की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षु बुनकर को 500 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति और 15,000 रुपए का करघा नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक सत्र में 6.8 लाख रुपए की राशि खर्च होगी।
- इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने कुम्हार हितग्राहियों को 13 लाख 20 हजार रुपए के 80 इलेक्ट्रिक चाक का वितरण भी किया, जिससे कुम्हार हितग्राही टेराकोटा, दीये, गुल्लक और विभिन्न तरह के मिट्टी की कलात्मक-सजावटी सामग्री का निर्माण कर अपने जीवन का निर्वहन आसानी से कर सकेंगे।
- इससे ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और कुम्हार आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर आम नागरिक भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखा रहे हैं और भविष्य में मिट्टी के उत्पादों का चलन बढ़ेगा।
- यह प्रशिक्षण केंद्र एक प्रभावी शुरुआत है और इससे न केवल कला और कौशल में निखार आएगा, बल्कि रोजगार में भी वृद्धि होगी। इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित युवक-युवतियाँ अपने भविष्य के लिये एक बेहतर दिशा तय कर सकेंगे।

- उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर केवल 2.1 प्रतिशत है, भविष्य में इसे और कम करने के लिये राज्य शासन द्वारा अन्य सकारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे। ऐसे प्रशिक्षण केंद्र और भी खोले जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा स्वावलंबी हो सकें और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें।

सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के भूमिहीन श्रमिकों ने गांधी 'सेवाग्राम' और छत्तीसगढ़ 'अमर जवान ज्योति' की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों?

- 3 फरवरी, 2022 को कॉन्ग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान सांसद राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में राज्य के भूमिहीन श्रमिकों ने महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिये नवा रायपुर में 'सेवाग्राम' और देश के लिये प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की याद में 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- सांसद राहुल गांधी के साथ 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' की आधारशिला रखने वाले श्रमिक हैं- रामकुमार निषाद (दुर्ग), खुजी मौर्य (बस्तर), सोना नेताम (बलौदाबाजार- भाटापारा) तथा मसियस तिर्की (बलरामपुर- रामानुजगंज)।
- राहुल गांधी ने रायपुर में राज्य शासन की महत्त्वाकांक्षी 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' और 'राजीव युवा मितान क्लब योजना' का शुभारंभ किया।
- राहुल गांधी ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार की तीन साल की उपलब्धियों पर प्रकाशित कॉफी-टेबल बुक 'जो कहा-सो किया' का विमोचन भी किया।
- उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त की राशि 3.55 लाख रुपए भूमिहीन परिवारों के खाते में ऑनलाइन अंतरित की। साथ ही राजीव युवा मितान योजना की राशि हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन अंतरित की।
- 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' का निर्माण छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की चौथी बटालियन, माना रायपुर में किया जाएगा।
- 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' देश के वीर सपूतों के बलिदान की स्मृतियों को संजोने, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली भावी पीढ़ियों के हृदय में जगाए रखने का प्रभावी माध्यम बनेगी।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के संदर्भ में कहा कि भूमिहीन मजदूरों को मदद पहुँचाने का यह देश में पहला उदाहरण है।
- इस योजना के माध्यम से खेत में काम करने वाले भूमिहीन मजदूरों, चरवाहों, नाई, धोबी, पुजारी, पुरोहित एवं पौनी-पसारी का काम करने वाले परिवारों को हर साल छह हजार रुपए की राशि मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर में बनने वाला 'सेवाग्राम' गांधीजी और गांधीवाद को समझने, महसूस करने, सीखने और याद रखने के लिये आधुनिक भारत के एक तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा।
- वर्धा का सेवाग्राम आश्रम गांधीजी के विचार, चिंतन, दर्शन और गांधीवाद के केंद्र में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है, वैसा ही नवा रायपुर सेवाग्राम एक उत्कृष्ट गांधीवादी केंद्र बनेगा।

छत्तीसगढ़ 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना को लागू करने वाला 35वाँ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मौजूदा समूह में छत्तीसगढ़ को शामिल किये जाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना को लागू करने वाला 35वाँ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि विभाग द्वारा ओएनओआरसी योजना के कार्यान्वयन की दिशा में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति की समीक्षा की गई थी। विभाग ने पोर्टेबिलिटी लेनदेन के सफल परीक्षण के बाद छत्तीसगढ़ को शामिल किये जाने की मंजूरी दी है।
- इसके अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिये ओएनओआरसी योजना को 2 फरवरी, 2022 से छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है।
- ओएनओआरसी के तहत छत्तीसगढ़ के प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी भी अब पूरे देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न की खरीद कर सकेंगे।
- छत्तीसगढ़ के शामिल होने के बाद 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ओएनओआरसी योजना का संचालन किया जा रहा है और देश की लगभग 96.8 फीसदी एनएफएसए जनसंख्या (करीब 77 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी) को कवर किया जा रहा है।
- ओएनओआरसी एक तकनीक संचालित वितरण प्रणाली है, जो पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को वहनीय बनाती है। यह प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों, जो अस्थायी रोजगार आदि की खोज में आमतौर पर लगातार अपने रहने की जगह बदलते रहते हैं, के लिये काफी लाभप्रद है। प्रवासी लाभार्थी परिवार के सदस्य, जो घर वापस आ चुके हैं, बिना किसी कठिनाई के बाकी राशन की खरीद कर सकते हैं।
- यह लाभार्थियों को अपने एकसमान/मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न की अपनी निश्चित मात्रा की खरीद का विकल्प प्रदान करता है।
- उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2019 में ओएनओआरसी योजना को शुरू किये जाने के बाद इसके तहत अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 56 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किये गए हैं। वहीं, अंतर-राज्य और राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटी लेनदेन के जरिये खाद्य सब्सिडी के रूप में 31,000 करोड़ रुपए के बराबर मूल्य के 100 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है।
- एक प्रमुख संकेतक के रूप में, वर्तमान में ओएनओआरसी के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिमाह औसतन लगभग 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन-देन (अंतर-राज्य, राज्य के भीतर और प्रधानमंत्री-जीकेएवाई खाद्यान्न लेन-देन सहित) दर्ज किया जा रहा है।

---

109 वर्षों बाद स्वतंत्रता सेनानी का अंतिम संस्कार

चर्चा में क्यों?

- 4 फरवरी, 2022 को स्वतंत्रता सेनानी लागुड़ नगेसिया की अस्थियों का 109 वर्षों बाद छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सामरी में ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया।

प्रमुख बिंदु

- बलरामपुर जिला स्थित राजेंद्रपुर के कुसमी ब्लॉक के लागुड़ नगेसिया ने बिगुड़ (बिगु बनिया) और थीथिर उराँव के साथ मिलकर वर्ष 1913 में अंग्रेजों के लिये काम करने वाले कई लोगों को मार डाला था।
- इस घटना के उपरांत थीथिर उराँव को ब्रिटिश आर्मी के घुड़सवार दल द्वारा तथा बिगुड़ और लागुड़ को गर्म तेल में डालकर मार डाला गया।
- इनमें से लागुड़ नगेसिया के कंकाल को अंबिकापुर के तत्कालीन एडवर्ड स्कूल (वर्तमान मल्टीपरपज स्कूल) में विज्ञान के विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाम पर रख दिया गया था, जो अब तक वहीं पर रखा हुआ था।
- स्वतंत्रता सेनानी लागुड़-बिगुड़ की कहानी सरगुजा क्षेत्र में लागुड़ किसान और बिगुड़ बनिया के रूप में आज भी प्रसिद्ध है।

छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 राजपत्र में प्रकाशित

चर्चा में क्यों?

- 4 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। नीति के तहत अलग-अलग श्रेणियों में अनुदान का प्रावधान किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े हजारों कलाकारों, टेक्निशियनों और निर्माता-निर्देशकों सहित स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नई फिल्म नीति 2021 तैयार की गई है।
- इस फिल्म नीति के तहत फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स और रियाल्टी शो तथा डाक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण, फिल्मांकन के लिये सुविधा व प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इससे फिल्म के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ को फिल्म अनुकूल राज्य बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन को राष्ट्रीय पहचान देना तथा यहाँ स्थानीय लोगों के लिये ज्यादा-से-ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

नरवा के उपचार से जल स्तर 1.6 मीटर तक बढ़ा

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में एक सरकारी सर्वेक्षण में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की महत्त्वाकांक्षी 'नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी' योजना के तहत राज्य के गाँवों में नालों के उपचार के कारण संबंधित गाँवों में कुओं और नलकूपों में भूजल स्तर 1.6 मीटर बढ़ गया है।

प्रमुख बिंदु

- एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पिछले तीन साल में राज्य के 2,477 नाले का उपचार किया गया। उपचार में स्टॉप डैम का निर्माण, मिट्टी के बोल्डर चेक, गली प्लग और ब्रश हुड का निर्माण शामिल है।
- उपचार कार्यों में 614 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई और राज्य भर में नाले को पुनर्जीवित किया गया।
- बयान में कहा गया है कि जिन गाँवों से ये नाले गुजरते हैं, उनका भूजल स्तर 0.20 से 1.60 मीटर के बीच बढ़ गया है। नाले के किनारे अपने खेत रखने वाले ग्रामीणों को लाभ हुआ और वे अब दोहरी फसलों के लिये जाने में सक्षम हैं।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का पिछला रिकॉर्ड टूटा

चर्चा में क्यों ?

- 7 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए धान खरीदी महाअभियान में राज्य सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर 97 लाख 97 हज़ार 122 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस साल राज्य में धान खरीदी एक दिसंबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक निर्धारित थी। बेमौसम बारिश की वजह से धान न बेच पाने वाले किसानों को धान बेचने का मौका दिये जाने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धान खरीदी की निर्धारित अवधि 31 जनवरी से बढ़ाकर 7 फरवरी कर दी गई थी।
- इस साल 21,77,283 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी धान बेची है, जो बीते वर्ष धान बेचने वाले 20,53,600 किसानों की संख्या से 1,23,683 अधिक है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते बीते तीन सालों में राज्य में धान उत्पादक कृषकों की संख्या और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके चलते समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का रिकॉर्ड साल-दर-साल टूट रहा है।
- किसानों की सहूलियत के लिये धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी 2311 से बढ़ाकर 2484 कर दी गई थी, जिससे किसानों को धान बेचने में आसानी हुई। किसानों के बारदाने के मूल्य को भी 18 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए किया गया।

- इस साल 97.97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है। वर्ष 2021 में 92 लाख मीट्रिक टन धान, वर्ष 2020 में 83.94 लाख मीट्रिक टन तथा 2019 में 80.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी।
- इस साल खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान बेचने के लिये कुल 24,06,560 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनके द्वारा बोए गए धान का रकबा 30 लाख 10 हज़ार 880 हेक्टेयर है, जबकि गत वर्ष पंजीकृत धान का रकबा 27 लाख 92 हज़ार 827 हेक्टेयर था।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल का वाज़िब मूल्य देने के साथ ही फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित की जा रही है। इसके चलते खेती से विमुख हो चुके लोग भी अब फिर से खेती की ओर लौटने लगे हैं, जिसके चलते राज्य में किसानों की संख्या, खेती के रकबे और फसल उत्पादकता में लगातार वृद्धि होती जा रही है।
- खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राजनांदगांव ज़िला प्रदेश में अग्रणी रहा है। राजनांदगांव ज़िले के 149 खरीदी केंद्रों में सर्वाधिक 8 लाख 25 हज़ार 127 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। जांजगीर-चांपा ज़िला 8 लाख 24 हज़ार 552 मीट्रिक टन धान का उपार्जन कर दूसरे क्रम पर तथा महासमुंद ज़िला 7 लाख 74 हज़ार 136 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर तीसरे क्रम पर रहा।
- बस्तर ज़िले में 1,58,915 मीट्रिक टन, बीजापुर में 63,703 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा में 17,437 मीट्रिक टन, कांकेर में 3,18,793 मीट्रिक टन, कोंडागांव में 1,53,322 मीट्रिक टन, नारायणपुर में 22,794 मीट्रिक टन, सुकमा में 46,291 मीट्रिक टन, बिलासपुर में 4,84,119 मीट्रिक टन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 69,356 मीट्रिक टन, कोरबा में 1,70,237 मीट्रिक टन, मुंगेली में 3,83,622 मीट्रिक टन, रायगढ़ में 5,72,898 मीट्रिक टन, बालोद ज़िले में 5,19,469 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है।
- इसी प्रकार बेमेतरा ज़िले में 6,30,616 मीट्रिक टन, दुर्ग में 4,17,097 मीट्रिक टन, कवर्धा में 4,16,281 मीट्रिक टन, बलौदाबाज़ार में 6,96,431 मीट्रिक टन, धमतरी में 4,31,397 मीट्रिक टन, गरियाबंद में 3,31,512 मीट्रिक टन, रायपुर में 5,09,931 मीट्रिक टन, बलरामपुर में 1,93,867 मीट्रिक टन, जशपुर में 1,54,181 मीट्रिक टन, कोरिया में 1,40,093 मीट्रिक टन, सरगुजा में 2,19,967 मीट्रिक टन और सूरजपुर ज़िले में 2,50,976 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है।
- अब तक 64.43 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। कस्टम मिलिंग करके भारतीय खाद्य निगम में 9.47 लाख मीट्रिक टन एवं नागरिक आपूर्ति निगम में 7.66 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है। इस साल किसानों से क्रय किये गए धान की एवज में उन्हें 19 हज़ार 83 करोड़ 97 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

देश के पहले आईडिया लैब का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- 8 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, रायपुर में देश के पहले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) आईडिया लैब का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि पूरे देश से कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आईडिया लैब स्थापित करने के लिये आवेदन किया था, जिनमें से 49 कॉलेजों का चयन किया गया। इनमें से एआईसीटीई ने रायपुर स्थित शंकराचार्य कॉलेज को चुना है।
- मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बुनियादी सिद्धांतों को समझाने और प्रयोग करके व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से आईडिया लैब की स्थापना की गई है। इस लैब की स्थापना से छात्रों को रिसर्च एवं इनोवेशन के लिये बेहतरीन सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कल्पना और सोच को मूर्त रूप देने में इस आईडिया लैब की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। इस लैब का उपयोग छात्र-छात्राओं के साथ-साथ आम लोग भी कर सकेंगे।

- नया उद्यम प्रारंभ करने वाले युवा इसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। किसी भी छात्र के पास कोई तकनीकी आईडिया हो तो वे इस लैब में आकर अपने सपने को साकार कर सकते हैं और अपने आईडिया को पेटेंट करा सकते हैं। उनके द्वारा डिजाईन किये गए प्रोडक्ट यहाँ विकसित हो सकेंगे। यह स्व-रोज़गार के क्षेत्र में बड़ा कदम होगा।
- साधन संपन्न प्रयोगशाला एवं विकसित सुविधाओं का उपयोग दूरस्थ अंचल के छात्र-छात्राएँ भी कर सकेंगे, ताकि वे सर्वांगीण विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भागीदारी निभा सकें।
- उल्लेखनीय है कि आईडिया लैब योजना के अंतर्गत देश के चुनिंदा संस्थानों में अनुदान दिया जाता है, जिससे संस्थान अत्याधुनिक उपकरणों की खरीदी करते हैं। इससे छात्रों के प्रशिक्षण में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती। आईडिया लैब से छात्रों के इनोवेशन एवं स्टार्टअप आईडिया को विकसित करने में सहायता मिलती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत आईडिया विकास, मूल्यांकन और अनुप्रयोगों को केंद्र में रखकर इस योजना को डिजाईन किया गया है। इससे छात्रों में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाईन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एवं कोलैबोरेशन जैसे स्किल्स का विकास होगा। यह लैब सातों दिन एवं 24 घंटे खुली रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के उर्वरक मांग में केंद्र ने की 45 फीसद की कटौती

चर्चा में क्यों?

- 8 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के रासायनिक उर्वरकों के डिमांड कोटे में केंद्र सरकार ने 45 फीसद की कटौती कर दी है। 7 लाख 50 हज़ार मीट्रिक टन के विरूद्ध केंद्र ने मात्र 4 लाख 11 हज़ार मीट्रिक टन उर्वरक प्रदाय किये जाने की स्वीकृति दी है, जिसके चलते राज्य में रासायनिक उर्वरकों की कमी की स्थिति निर्मित हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ राज्य को चालू रबी सीजन के लिये केंद्र सरकार द्वारा मांग के अनुसार रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति न करने के कारण प्रदेश में किसानों को रासायनिक खादों को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद राज्य के किसानों को रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता के आधार पर सोसायटियों से खाद उपलब्ध कराई जा रही है।
- चालू रबी सीजन के लिये विभिन्न प्रकार के कुल 7 लाख 50 हज़ार मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की डिमांड भारत सरकार से की गई है, परंतु आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य को मात्र 3 लाख 20 हज़ार मीट्रिक टन उर्वरक ही मिला है।
- छत्तीसगढ़ राज्य को अब तक यूरिया 1,17,522 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है, जो राज्य की मांग का मात्र 34 प्रतिशत है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य को मांग का डीएपी मात्र 28 प्रतिशत, पोटाश 53 प्रतिशत, एनपीके काम्प्लेक्स 43 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल रबी सीजन में 18 लाख 50 हज़ार हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बुआई का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 15 लाख 76 हज़ार हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है।
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केंद्र सरकार को 7.50 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की मांग भेजी गई थी, जिसमें यूरिया 3.50 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 2 लाख मीट्रिक टन, पोटाश 50 हज़ार मीट्रिक टन, एनपीके काम्प्लेक्स 75 हज़ार मीट्रिक टन एवं सुपर फास्फेट (राखड़) 75 हज़ार मीट्रिक टन है, जिसके विरूद्ध केंद्र सरकार द्वारा 4,11,000 मेट्रिक टन की स्वीकृति दी गई, जो छत्तीसगढ़ राज्य की मांग का 55 प्रतिशत है। यह राज्य की मांग के अपेक्षा काफी कम है।
- राज्य को चालू रबी सीजन के लिये सहकारिता क्षेत्र में 93,214 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त मात्रा 1,52,027 मीट्रिक टन से 39 प्रतिशत कम है। यूरिया 31,500 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत कम है। डीएपी 19,434 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में 68 प्रतिशत कम है। पोटाश 4,191 मीट्रिक टन मिला है, जो गत वर्ष की 15,847 मीट्रिक टन की तुलना में 74 प्रतिशत कम है। इसी तरह एनपीके की भी गत वर्ष की तुलना में कम आपूर्ति हुई है।

नोट :

राज्य में शुरू हुआ 'सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0'

चर्चा में क्यों ?

- 7 फरवरी, 2022 को नियमित टीकाकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 'सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0' की शुरुआत की गई। फिलहाल इसकी शुरुआत राज्य के पाँच ज़िलों- बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर एवं राजनांदगाँव से की गई है।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत उक्त पाँचों ज़िलों में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं एवं मितानिनों द्वारा गृह भ्रमण कर नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों का चिन्हांकन कर सूची बनाई गई है।
- अभियान के अंतर्गत जन्म से 2 वर्ष तक के 5 हज़ार 435 बच्चे एवं 2 हज़ार 604 गर्भवती माताओं को टीकाकृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के जरिये नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों को टीका लगाया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि यह अभियान राज्य में 3 चरणों में संचालित किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण 7 फरवरी से 13 फरवरी द्वितीय चरण 07 मार्च से 13 मार्च एवं तृतीय चरण 4 अप्रैल से 10 अप्रेल तक संचालित किये जाएंगे। प्रत्येक चरण सात दिवस के होंगे।
- अभियान में उन गर्भवती माताओं को शामिल किया गया है, जो किन्ही कारणों से टीडी 1, टीडी 2 और बूस्टर टीडी के टीके नहीं लगवा पाई हैं। अभियान के तहत नियमित टीकाकरण से छूटे जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को बीसीजी, पोलियो, डिप्थेरिया, टिटनेस, कुकुर खाँसी, हेपेटाइटिस-बी, हिमोफिलियस, इन्फ्लुएंजा-बी, रोटावायरस, निमोनिया, दिमागी बुखार, खसरा, रूबेला, एवं जैपजीन, इन्सेफेलाइटिस के टीके लगाए जा रहे हैं।
- राज्य में चिह्नित ज़िलों में प्रथम चरण में 2199 सत्र आयोजित किये जाएंगे, जिससे 5400 से अधिक 02 वर्ष तक के बच्चे एवं 2600 से अधिक गर्भवती माताएँ टीकाकृत होंगी। सभी टीकाकरण सत्र ज़िलों के चिन्हाकित ग्रामों के आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किये जाएंगे।

शासकीय विभागों को अब 10 प्रतिशत छूट के साथ मिलेंगे 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के उत्पाद

चर्चा में क्यों ?

- 9 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के समस्त विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देशित किया है कि 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' ब्रांड के अंतर्गत निर्मित उत्पादों को एमआरपी पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ लेते हुए शासकीय खरीदी किये जाने की व्यवस्था लागू करें।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य शासन के समस्त विभागों, शासकीय उपक्रमों तथा नगर निगमों आदि संस्थाओं को 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' ब्रांड के उत्पादों को अपनी आवश्यकतानुसार छूट के साथ अनिवार्य रूप से क्रय करने के निर्देश दिये गए हैं।
- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को निर्धारित दर पर सीधे क्रय किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2020) के नियम 8 में संशोधन किया गया है।
- मुख्य सचिव द्वारा समस्त शासकीय संस्थाओं को ऐसी सभी सामग्रियों, जिनका विक्रय 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' ब्रांड के अंतर्गत संजीवनी केंद्रों के माध्यम से किया जाता है, उनका अनिवार्य रूप से एमआरपी पर 10 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स', छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार और विकास) सहकारी संघ की एक इकाई है, जो राज्य में जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों, विशेषकर आदिवासियों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ 61 लघु वनोपज खरीदता है और 150 से अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन कर रहा है। संघ ने उत्पादों की खुदरा बिक्री के लिये राज्य के सभी प्रमुख ज़िलों में 30 संजीवनी केंद्र स्थापित किये हैं।

नोट :

- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय स्तर की प्रदर्शनियों में 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' की उपस्थिति ने विश्व स्तर पर उत्पादों की पहुँच का विस्तार किया है। 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय गल्फ फूड फेस्टिवल, दिल्ली में इंटरनेशनल इंडसफूड इवेंट, दिल्ली में ट्राइबल फेस्टिवल, भोपाल में इंटरनेशनल हर्बल फेयर, छत्तीसगढ़ दिवाली हाट मेला, राज्योत्सव और मॉल में प्रदर्शनियों में भाग लिया था।
- इसके अलावा सरकारी और निजी संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में समय-समय पर 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' की प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं।

प्रदेश में कोदो-कुटकी-रागी के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

चर्चा में क्यों ?

- 9 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित मिलेट मिशन की अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में 'मिलेट मिशन' के तहत प्रदेश में कोदो-कुटकी और रागी के उत्पादन रकबे में बढ़ोतरी के लिये कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में वर्तमान में 69 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। अगले खरीदी वर्ष तक फसल उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ाकर एक लाख 17 हज़ार हेक्टेयर किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कोदो-कुटकी-रागी की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इस खरीदी वर्ष में अब तक 27 हज़ार क्विंटल मिलेट्स की खरीदी की जा चुकी है।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत कोदो 30 रुपए, कुटकी (काला) 30 रुपए, कुटकी (भूरा) 30 रुपए, रागी 33.77 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी जा रही है।
- राज्य में समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी किये जाने की निर्धारित तिथि 1 दिसंबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक थी, जिसे हाल ही में 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब 61 लघु वनोपजों की खरीदी

चर्चा में क्यों ?

- 8 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये लघु वनोपजों की संख्या 52 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग तीन वर्ष में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़कर 61 हो गई है।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत 52 से बढ़ाए गए 61 लघु वनोपजों में हर्रा बाल, महुआ फूल कच्चा (फूड ग्रेड), झाड़ू छिंद (घास), कोदो, कुटकी (काला), कुटकी (भूरा), रागी, अमचूर (सफेद) तथा अमचूर (भूरा) नवीन लघु वनोपज शामिल हैं।
- निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार इनमें हर्रा बाल 30 रुपए, महुआ फूल कच्चा (फूड ग्रेड) 10 रुपए, झाड़ू छिंद (घास) 15 रुपए, कोदो 30 रुपए, कुटकी (काला) 30 रुपए, कुटकी (भूरा) 30 रुपए, रागी 33.77 रुपए, अमचूर (सफेद) 120 रुपए तथा अमचूर (भूरा) 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि राज्य में वर्तमान में समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदी की जा रही लघु वनोपजों में मालकांगनी बीज (सूखा), बायबडिंग, कालमेघ/भूईनीम (सूखा), आँवला (बीज रहित) सूखा, रंगीनी लाख/छिली लाख (सूखा), रीठा फल (सूखा), वन जीरा बीज, सतावर जड़ (सूखा), चरौटा बीज, शहद तथा नागरमोथा (सूखा) शामिल हैं।

- इसी तरह माहुल पत्ता, हर्रा साबूत (सूखा), हर्रा कचरिया, बहेड़ा साबूत (सूखा), बहेड़ा कचरिया, गिलोय (सूखा), कुसुमी लाख/छिली लाख (सूखा), वन तुलसी बीज, भेलवा, शिकाकाई फल्ली (सूखा), इमली आटी (बीज सहित), इमली फूल (बीज रहित), इमली बीज, महुआ फूल (सूखा), महुआ बीज, झाड़ू फूल (घास), कौंच बीज, धवई फूल (सूखा), चिरौंजी गुठली, करंज बीज, बेलगुदा (सूखा), कुल्लू गोंद, काजू गुठली, साल बीज, कुसुम बीज, नीम बीज (सूखा) तथा जामुन बीज (सूखा) की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है।
- इसके अलावा आँवला फल (कच्चा), रंगीनी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ), कुसुमी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ), झाड़ू कांटा (घास), बेलफल (कच्चा), जामुन फल (कच्चा), सवई घास, पाताल कुम्हड़ा कंद (सूखा), सफेद मूसली कंद (सूखा), तीखुर कंद (कच्चा), अश्वगंधा जड़ (सूखा), कोरिया बीज (इंद्र जौ) (सूखा), कुटज छाल (सूखा) तथा पलाश फूल (सूखा) की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है।

सबके लिये आवास मिशन

चर्चा में क्यों?

- 10 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में हुई 'प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास मिशन (शहरी)' की राज्यस्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में राज्यस्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा राज्य में योजना के तहत 12 हज़ार 60 आवासों के निर्माण का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को योजना के तहत आवासों की बुकिंग को आवंटन के लिये प्राथमिकता का आधार निर्धारित करने के निर्देश दिये।
- राज्य में सबके लिये आवास मिशन (शहरी) आवास के अंतर्गत 12060 आवासों का निर्माण 374 करोड़ 93 लाख 12 हज़ार रुपए की लागत से कराया जाएगा। प्रत्येक आवास की लागत 3.05 लाख रुपए होगी।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिये 'प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास मिशन' जून 2015 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने की अधिसूचना

चर्चा में क्यों?

- 10 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने तथा भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर एवं 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने हेतु 'औद्योगिक नीति-2019-24' में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने तथा भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर एवं 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी।
- जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये इस प्रवर्ग हेतु 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किये जाएंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

- आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक रहेगी।
- भूखंड-भूमि की मात्रा 'छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015' में वर्णित पात्रता के नियम तथा प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

'ओरो स्कॉलर'और 'प्रोजेक्ट इन्क्ल्यूजन' कार्यक्रम शुरू

चर्चा में क्यों?

- 11 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने निवास कार्यालय में राज्य के कक्षा पहली से बारहवीं तक के स्कूली बच्चों के लिये 'ओरो स्कॉलर'और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिये 'प्रोजेक्ट इन्क्ल्यूजन'कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- ओरो स्कॉलर कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे क्विज प्रतियोगिता में शामिल होकर हज़ारों रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकेंगे।
- इसी प्रकार प्रोजेक्ट इन्क्ल्यूजन कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ लाने के लिये है।
- ये दोनों कार्यक्रम श्री अरबिंदो सोसायटी के माध्यम से संचालित किये जाएंगे।
- मंत्री डॉ. टेकाम ने बताया कि ओरो स्कॉलर कार्यक्रम कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिये है। इसमें बच्चे ओरो स्कॉलर ऐप में अपना पंजीयन कर 20 क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। प्रत्येक क्विज में 80 प्रतिशत अंक लाने पर उन्हें 50 रुपए प्राप्त होंगे। 20 क्विज में से सभी में 80 प्रतिशत अंक लाने पर एक माह में बच्चे को एक हज़ार रुपए मिलेंगे।
- क्विज से प्राप्त पैसों से बच्चे न केवल आगे की पढ़ाई का खर्च स्वयं वहन करने में सक्षम हो सकेंगे, बल्कि अपने परिवार को भी आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकेंगे।
- प्रोजेक्ट इन्क्ल्यूजन कार्यक्रम के अंतर्गत अरबिंदो सोसायटी द्वारा शिक्षकों को शारीरिक और मानसिक रूप से किसी-न-किसी रोग से ग्रस्त बच्चों की पहचान करना तथा उनके कमज़ोर क्षेत्रों को कैसे सुधारा जाए, इसकी जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाएगी। शिक्षक प्रशिक्षण लेने के बाद ऐसे बच्चों की पहचान कर उनकी खामियों को दूर कर उन्हें सामान्य बच्चों की तरह ही सीखने लायक बना सकेंगे।

छत्तीसगढ़ में नौनिहालों के लिये की जाएगी 'बालवाड़ी'की स्थापना

चर्चा में क्यों?

- 11 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में नौनिहालों की शिक्षा और शिक्षा स्तर में सुधार के लिये नई शिक्षा नीति के तहत 'बालवाड़ी'की स्थापना की जाएगी। इन बालवाड़ी केंद्रों में खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से नौनिहालों के सीखने पर ज़ोर दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले चरण में राज्य भर में छह हज़ार से अधिक बालवाड़ी केंद्रों की स्थापना की घोषणा हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर की थी।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के अंतर्गत 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिये ऐसे स्थानों पर प्ले स्कूल 'बालवाड़ी'की स्थापना की जाएगी, जहाँ आंगनवाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में हों।
- प्रथम चरण में ऐसी 6 हज़ार से अधिक बालवाड़ी प्रारंभ की जाएंगी। राज्य में ऐसे केंद्रों की संख्या 6536 है, जहाँ प्राथमिक शालाएँ आंगनवाड़ी में ही स्थित हैं। प्रस्ताव के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही बालवाड़ी (बालवाटिका) का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
- बालवाड़ी में प्रवेश के लिये 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की अनुमानित संख्या एक लाख 15 हज़ार है। इन बच्चों के लिये एससीईआरटी ने बालवाटिका गतिविधि पुस्तिका भी तैयार कर ली है।

नोट :

- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नई पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिये स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा तक और रोज़गार से लेकर संस्कार विकसित करने तक अनेक कदम उठाए हैं।
- प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को भी भविष्य में बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिये स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम शालाओं की स्थापना की गई है। राज्य में अभी 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम शालाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें 20 हज़ार से अधिक बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा दी जा रही है। इसी तरह ऐसी हिन्दी शालाओं की स्थापना भी प्रत्येक ज़िले में की जाएगी।

रायपुर और दिल्ली में खुलेगा बस्तर कैफे

चर्चा में क्यों?

- 14 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ टी-कॉफी बोर्ड की बैठक में बस्तर में उत्पादित कॉफी के विक्रय सह-मार्केटिंग के लिये रायपुर एवं नई दिल्ली में बस्तर कैफे प्रारंभ किये जाने की पहल की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में बस्तर एवं सरगुजा संभाग में चाय और कॉफी की खेती के रकबे को विस्तारित करने तथा बस्तर में उत्पादित कॉफी की मार्केटिंग के लिये प्राइवेट कंपनियों से एमओयू किये जाने का निर्णय लिया गया।
- बस्तर में उत्पादित कॉफी के लिये विक्रय सह-मार्केटिंग फिलहाल जगदलपुर में बस्तर कैफे का संचालन किया जा रहा है।
- मंत्री रविंद्र चौबे ने बस्तर सहित राज्य के सरगुजा संभाग के पठारी इलाकों में चाय एवं कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिये सर्वे कर प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि बस्तर में उत्पादित कॉफी की मार्केटिंग के लिये निजी कंपनियों से इस शर्त के साथ एमओयू किया जाए कि कॉफी के ब्रांडनेम में बस्तर का नाम अनिवार्य रूप से शामिल होगा।
- उन्होंने इसकी प्रोसेसिंग के लिये मशीन की स्थापना हेतु आवश्यक राशि का प्रबंध डीएमएम फंड से सुनिश्चित किये जाने की बात कही। साथ ही अधिकारियों को सुकमा ज़िले में भी कॉफी की खेती के लिये एरिया चिह्नांकित करने के निर्देश दिये।
- दरभा में 20 एकड़ में लगाए गए कॉफी प्लांटेशन से उत्पादन होने लगा है। प्रथम चरण में 8 क्विंटल कॉफी का उत्पादन हुआ है, जिसका उपयोग जगदलपुर में संचालित बस्तर कैफे के माध्यम से किया जा रहा है, जहाँ प्रतिदिन दो किलो कॉफी की खपत हो रही है। उत्पादित मात्रा के उपयोग एवं मार्केटिंग के लिये कम-से-कम तीन कैफे और प्रारंभ किये जा सकते हैं। बस्तर कॉफी की ब्रांडिंग के लिये रायपुर एवं दिल्ली में एक-एक कैफे शुरू किये जाने की बात कही गई।
- बैठक में बताया गया कि बस्तर के दरभा में वर्ष 2021 में 55 एकड़ में कॉफी की खेती की गई है। बस्तर ज़िले में अभी कुल 5108 एकड़ में कॉफी की खेती प्रस्तावित है।
- गौरतलब है कि बस्तर ज़िले में प्रतिवर्ष 1000 एकड़ में कॉफी की खेती को विस्तारित किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2026 तक 5820 एकड़ में इसकी खेती होने लगेगी।
- बैठक में जशपुर ज़िले में चाय की खेती को बढ़ावा देने की कार्ययोजना तथा टी-कॉफी उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधनों के संबंध में भी चर्चा की गई।

राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन

चर्चा में क्यों?

- 14 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी कर राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- शासी निकाय का अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तथा उपाध्यक्ष खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल को बनाया गया है।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, लोकसभा सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, विधायक देवेंद्र यादव, विधायक विनय भगत, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को सदस्य तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 15 से 40 वर्ष आयु के युवाओं के लिये राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की गई है, जिसके तहत युवा मितान क्लब बनाए गए हैं।
- युवा मितान क्लब के माध्यम से पर्यावरण, खेल और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में युवा मितान क्लब गठित किये जा रहे हैं।

राज्य में चलेगा 'टेबलेट से पहले टॉयलेट अभियान'

चर्चा में क्यों ?

- 15 फरवरी, 2022 को मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आगामी शिक्षा सत्र में टेबलेट के पहले टॉयलेट अभियान को मूर्तरूप देने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग की समग्र शिक्षा कार्यकारिणी समिति और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना के क्रियान्वयन के लिये गठित राज्यस्तरीय मॉनीटरिंग सह संचालन समिति की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने की।
- इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक-एक स्कूल में आदर्श शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इन शौचालयों में कम लागत में अच्छी गुणवत्ता का निर्माणकार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
- शौचालयों में रनिंग वाटर, ड्रेनेज आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इनकी नियमित साफ-सफाई और रख-रखाव के लिये विशेष प्रबंध किये जाएंगे। इन शौचालयों का निर्माण विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समन्वय से किया जाएगा।
- मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री सहित अन्य सामग्रियों की खरीदी गौठानों में संचालित ग्रामीण आजीविका केंद्र से किये जाने के निर्देश दिये।
- बैठक में शिक्षण सत्र 2022-23 के लिये समग्र शिक्षा के तहत 3456.98 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना और मध्याह्न भोजन योजना के लिये कुल 696.18 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। अनुमोदन के पश्चात् यह प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिये भेजे जाएंगे।

कमिश्नर ने किया स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 15 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने तरण पुश्कर मैदान में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो तथा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- एक्सपो में 7 राज्यों से आए बुनकरों की हथकरघा कला को खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विविध कार्यक्रमों की कड़ी में किया गया। यह प्रदर्शनी आगामी 27 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक प्रदर्शनी खुली रहेगी।

नोट :

- कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने शुभारंभ के बाद विभिन्न स्टॉलों का दौरा कर बुनकर कलाकारों से मुलाकात की एवं वस्त्र प्रदर्शनी के नमूनों का अवलोकन किया।
- प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के हथकरघा विकास आयुक्त तथा संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम भोपाल द्वारा स्थानीय ज़िला प्रशासन के सहयोग से किया गया है।
- प्रबंध संचालक अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि हथकरघा कलाकारों की प्रतिभा को निखारने एवं उन्हें बाज़ार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है।
- प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बुनकर कलाकार भागीदारी कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ज़िले में आत्मानंद हिन्दी स्कूल खोलेगा

चर्चा में क्यों?

- 16 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों की लोकप्रियता के बाद, प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक हिन्दी माध्यम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- आगामी शैक्षणिक सत्र से हिन्दी माध्यम के कुल 32 नए स्कूल अस्तित्व में आएंगे। निर्धारित स्कूलों के भवनों का नवीनीकरण किया जाएगा और स्कूलों को गुणात्मक के साथ सौंदर्य की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा।
- स्वामी आत्मानंद के नाम पर स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 74 हज़ार छात्रों के साथ 171 अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल चल रहे हैं। जिसमें राज्य की राजधानी रायपुर में में ऐसे कुल तीन अंग्रेज़ी स्कूल शुरू किये गए हैं। इन विद्यालयों की स्थापना एक बड़ी सफलता सिद्ध हुई। पहले रायपुर के आरडी तिवारी स्कूल (हिन्दी) में केवल 57 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन इसे स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल के रूप में अपग्रेड करने के बाद, इसमंन 1,000 छात्र हैं।
- इन स्कूलों में दाखिल बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से हैं। छात्रों की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का पूरा खर्च सरकार वहन करती है।

तीन नदियों के संगम पर शुरू हुआ 'राजिम माघी पुन्नी मेला'

चर्चा में क्यों?

- 16 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने 'राजिम माघी पुन्नी मेला'का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- 'राजिम माघी पुन्नी मेला' तीन नदियों (त्रिवेणी) के संगम पर शुरू हुआ, जिसमें भक्तों ने पवित्र स्नान किया और देवताओं की पूजा की। इसका समापन 1 मार्च को होगा।
- उल्लेखनीय है कि राजिम शहर और उसका मंदिर तीन नदियों- सोंदूर, पर्री और महानदी के संगम पर स्थित है जिसे छत्तीसगढ़ का 'प्रयागराज'माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 'माघ पुन्नी' के दौरान, भक्त संगम पर पवित्र डुबकी लगाते हैं।
- त्रिवेणी आरती के रचनाकार पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री ने बताया कि माघ के महीने में सभी नदियों का जल गंगा स्वरूप हो जाता है और महानदी तो साक्षात् गंगा है। पुराणों में चित्रोत्पला कहकर इसकी स्तुति की गई है। त्रेतायुग में जगदंबा जानकीजी के द्वारा श्रीराम वनगमनकाल में इसके संगम के बीचोबीच बालू की रेत से शिवलिंग प्रतिष्ठापित किया गया था और उनका चित्रोत्पलेश्चर कहकर पूजन-अभिषेक किया गया था, जो कालांतर में कुलेश्वर हो गया।

- इस मेले में राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले संतों को 'संत निवास' प्रदान किया गया है।
- इस 14 दिवसीय मेले के लिये विशेष परिवहन और स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और पार्किंग क्षेत्र सुनिश्चित किया गया है।
- इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएंगे, जिसके लिये राजीव लोचन मंदिर के पास मंच बनाया गया है।

तालाब गहरीकरण के दौरान प्राप्त हुई योग नरसिंह की विरल प्राचीन मूर्ति

चर्चा में क्यों ?

- 17 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले के आरंग विकासखंड के अंतर्गत ग्राम कुम्हारी में तालाब गहरीकरण के दौरान प्राप्त योग नरसिंह की विरल प्राचीन मूर्ति को संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग द्वारा रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाया गया।

प्रमुख बिंदु

- योग नरसिंह की यह प्राचीन मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और 4थी-5वीं सदी ईसवी की आँकी जा रही है। तालाब खुदाई के दौरान गुप्तकालीन पात्र परंपरा के मृद्भांड भी पाए गए हैं।
- गौरतलब है कि 15 फरवरी को सोशल मीडिया में प्रसारित ग्राम कुम्हारी ज़िला रायपुर से खुदाई में दौरान नरसिंह की प्राचीन प्रतिमा मिलने की खबर के आधार पर संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने विभागीय अधिकारियों की टीम बनाकर प्राप्त प्रतिमा और उसके प्राप्ति स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिये थे।
- उप संचालक डॉ. पी.सी. पारख के नेतृत्व में पुरातत्त्ववेत्ता प्रभात कुमार सिंह, उत्खनन सहायक प्रवीन तिर्की की टीम कुम्हारी गाँव पहुँची और मूर्ति एवं प्राप्ति स्थल का मुआयना किया। बस्ती के उत्तर में बघधरा नामक देवस्थल के पास स्थित भाठा ज़मीन यह मूर्ति प्राप्त हुई थी।
- पुरातत्त्व विभाग के अनुसार यह अनूठी और विरल प्राप्त होने वाली मूर्ति है। इसे नरसिंह अथवा शांत नरसिंह भी कहा जाता है। ऐसी मुद्रा में देवता अकेले शांत बैठे हुए प्रदर्शित किये जाते हैं। आमतौर पर हिरण्यकश्यप का वध करते (पेट फाड़ते) हुए नरसिंह मूर्ति बहुतायत में मिलती है, लेकिन नरसिंह की इस रूप की प्रतिमा का शिल्पांकन अपेक्षाकृत कम हुआ है।
- लाल बलुआ पत्थर निर्मित इस मूर्ति का आकार 18×12.5×02 सेंटीमीटर है, जिसका निचला भाग अंशतः खंडित है।

गढ़कलेवा चौपाटी का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 17 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी ज़िला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ी एवं स्थानीय व्यंजनों के लिये गढ़कलेवा चौपाटी शुरू करने के निर्देश दिये। इसी कड़ी में ज़िला मुख्यालय बलरामपुर में सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह ने गढ़कलेवा चौपाटी का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- शुभारंभ के अवसर पर विधायक बृहस्पत सिंह ने महिला स्व-सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ज़िला मुख्यालय में गढ़ कलेवा चौपाटी की शुरुआत की गई है।
- ज़िला मुख्यालय में गढ़कलेवा चौपाटी खुलने से लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ-साथ स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद ले पाएंगे।
- इस गढ़कलेवा चौपाटी में लक्ष्मी स्वसहायता समूह, आम स्वसहायता समूह, जीवन पालन स्वसहायता समूह, दुर्गा स्वसहायता समूह एवं शिवशक्ति स्वसहायता समूह द्वारा विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं।

नोट :

राज्य में 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये शुरू होगी 'बालवाड़ी' योजना

चर्चा में क्यों ?

- 18 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के 6536 स्कूलों के परिसर में, जहाँ आंगनवाड़ियाँ संचालित हैं, वहाँ अब 'बालवाड़ी' भी प्रारंभ की जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- यह 'बालवाड़ी' प्री-स्कूल की तरह संचालित होंगी, जहाँ 5 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को शैक्षणिक एवं खेल के माध्यम से शिक्षा मिलेगी।
- राज्य शासन का यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। 'बालवाड़ी' नाम से संचालित होने वाली इस योजना के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 68 हज़ार 54 बच्चे लाभान्वित होंगे।
- 'बालवाड़ी' के संचालन के लिये बच्चों की सामग्री 'बालवाटिका' तैयार की जा चुकी है। शिक्षकों की प्रशिक्षण की तैयारी कर ली गई है। बालवाड़ी का संचालन स्कूल परिसर में भोजन अवकाश के पूर्व दो घंटे किया जाएगा।
- इन स्थानों पर इस योजना को संचालित किये जाने से शालापूर्व ही बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को बेहतर करने के लिये आधार प्राप्त होगा, जो प्राथमिक स्तर में बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने में नींव का पत्थर साबित होगा।
- राज्य के 5-6 वर्ष के आयु समूह के 3 लाख 23 हज़ार 624 विद्यार्थियों में से 68 हज़ार 54 विद्यार्थी इसी सत्र (2022-23) से लाभान्वित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 26 जनवरी, 2022 को गणतंत्र दिवस पर जनता के नाम अपने संदेश में 'बालवाड़ी' के संचालन की घोषणा की गई थी, उसी के अनुरूप यह योजना शुरू की जा रही है।
- प्रदेश में कुल प्राथमिक स्कूलों की संख्या 30 हज़ार 574 और आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 52 हज़ार 474 है। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र, जो स्कूल परिसर में ही स्थित हैं, उनकी संख्या 6 हज़ार 536 है। इन स्थानों पर तत्काल बालवाड़ी के नाम से 5-6 वर्ष के बच्चों के लिये शैक्षणिक और खेल के माध्यम से प्री-स्कूल प्रारंभ किये जाने हैं। आगामी समय में चरणवार योजना का विस्तार किया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 69.50 लाख राशन कार्ड जारी

चर्चा में क्यों ?

- 20 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2016 के अंतर्गत अब तक कुल 69 लाख 50 हज़ार 49 परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इन जारी राशनकार्ड में अंत्योदय के परिवार, निराश्रित, नि:शक्तजन, प्राथमिकता वाले परिवार एवं एपीएल परिवार शामिल हैं।
- राशनकार्ड धारियों में 54 लाख 60 हज़ार 678 परिवार ग्रामीण क्षेत्र के तथा 14 लाख 89 हज़ार 371 परिवार शहरी क्षेत्र के हैं।
- राज्य में प्राथमिकता वाले 45 लाख 5 हज़ार 867 परिवारों को, अंत्योदय के 14 लाख 21 हज़ार 585 परिवारों को तथा 38 हज़ार 645 निराश्रितों को राशन कार्ड जारी किया गया है।
- कार्डधारी नि:शक्तजन की संख्या 11 हज़ार 483 तथा एपीएल सामान्य परिवार वाले राशन कार्डधारी की संख्या 14 लाख 89 हज़ार 371 है।
- गौरतलब है कि राज्य में पात्र छूटे हितग्राहियों को नियमानुसार राशन कार्ड जारी किये जा रहे हैं।

नोट :

छत्तीसगढ़ के आकांक्षी और हाईबर्डन ज़िले में होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण

चर्चा में क्यों?

- 21 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आकांक्षी ज़िलों और हाईबर्डन ज़िलों में कुपोषण एवं एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिये फोर्टिफाइड चावल के वितरण का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 आंकाक्षी ज़िलों और 2 हाईबर्डन ज़िलों में मार्च 2022 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य योजना के राशनकार्डधारी परिवारों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। राइस फोर्टिफिकेशन का शत-प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य योजना के राशनकार्डों में चावल का वार्षिक आवंटन लगभग 3 लाख 89 हज़ार 486 टन है। इस चावल के फोर्टिफिकेशन के लिये लगभग 28.43 करोड़ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिये राज्य सरकार द्वारा 11.16 करोड़ रुपए इस प्रकार की 39.59 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी।
- फोर्टिफाइड चावल का वितरण राज्य के 10 आकांक्षी ज़िले- कोरबा, राजनांदगाँव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागाँव, सुकमा तथा 2 हाईबर्डन ज़िलों कबीरधाम और रायगढ़ में किया जाएगा।
- इन ज़िलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डों की तरह ही राज्य योजना के राशनकार्डों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा।
- गौरतलब है कि 'फोर्टिफाइड' चावल आयरन और विटामिन से युक्त होता है। इस चावल में विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी12, फोलिक एसिड, आयरन और ज़िंक, सभी पोषक तत्त्व का मिश्रण होता है। यह लोगों की खुराक में आवश्यक पौष्टिक तत्त्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण के नियंत्रण में काफी हद तक मददगार होता है।

विशेष प्रोत्साहन पैकेज में अब प्लास्टिक एवं टेक्सटाइल्स उद्योग भी शामिल

चर्चा में क्यों?

- हाल में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक और टेक्सटाइल क्षेत्र के दो उद्योगों को विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- जिन दो उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का अनुमोदन किया गया है उनमें प्लास्टिक गुड्स मैन्युफेक्चरिंग प्लांट एवं नॉनओवन इंटरलाइनिंग फैब्रिक उद्योग शामिल हैं।
- प्लास्टिक गुड्स मैन्युफेक्चरिंग प्लांट लगाने के लिये मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के साथ 107.73 करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है, जिसमें लगभग 200 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- इसी प्रकार मेसर्स एसबीटी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के द्वारा नॉनओवन इंटरलाइनिंग फैब्रिक उद्योग लगाने के लिये 22.15 करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है। इस टेक्सटाइल्स उद्योग की स्थापना से लगभग 220 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- 'बी स्पोक पॉलिसी' के तहत विशेष प्रोत्साहन पैकेज में राज्य के कोर सेक्टर के लौह-इस्पात, सीमेंट एवं बिज़ली के उद्योगों को पहले ही शामिल कर लिया गया है।
- 'बी-स्पोक पॉलिसी' के तहत प्लास्टिक और टेक्सटाइल के दो उद्योगों के लगने से राज्य में लगभग 400 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योग के लिये क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक दी गई है।

नोट :

ई-पास के ज़रिये अब खाद्यान्न का वितरण

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में मार्च महीने से ई-पास के ज़रिये खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विभाग ने माह फरवरी का खाद्यान्न वितरण ई-पास उपकरण के साथ-साथ टैबलेट के माध्यम से भी किये जाने के निर्देश दिये हैं।
- ज्ञातव्य है कि राज्य में 13 हज़ार 294 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिनमें 12 हज़ार 322 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई-पास उपकरण स्थापित किया जा चुका है।
- इन दुकानों में माह मार्च 2022 से खाद्यान्न का वितरण टेबलेट की जगह ई-पास उपकरण के माध्यम से किया जाएगा। शेष 972 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पास उपकरण स्थापित होने तक टैबलेट के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।
- प्रदेश के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा ज़िले को छोड़कर शेष 24 ज़िलों की ई-पास स्थापित 12 हज़ार 322 उचित मूल्य दुकानों के राशन कार्डधारियों को इन ज़िलों में अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
- ऐसे राशन कार्डधारी, जिनमें किसी भी सदस्य का आधार नंबर सत्यापित नहीं अथवा अप्राप्त है, उनके आधार नंबर की जानकारी तत्काल प्राप्त कर विभागीय वेबसाइट में दर्ज कराने के निर्देश दिये गए हैं।
- ऐसे राशन कार्डधारी, जिनमें किसी भी सदस्य का आधार सत्यापित है, परंतु ई-पास उपकरण के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण असफल हो रहा है, ऐसे राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण हेतु नॉमिनी (प्रतिनिधि) के निर्धारण के लिये ज़िला कलेक्टर के माध्यम से खाद्य संचालनालय को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। संचालनालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद ज़िला स्तर पर खाद्य अधिकारी द्वारा अन्य हितग्राही को नॉमिनी नियुक्त करने के पश्चात् नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।
- नि:शक्त, 60 वर्ष से अधिक अथवा 10 वर्ष से कम आयु के राशन कार्डधारियों के लिखित आवेदन पर ज़िला स्तर पर खाद्य अधिकारी द्वारा नियुक्त हितग्राही को नॉमिनी नियुक्त कर हुए नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।
- सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में मासिक आवंटन के अनुसार चावल, शक्कर, चना, नमक, गुड़ एवं केरोसिन का भंडारण वितरण माह के प्रथम तारीख से पहले अनिवार्य रूप से प्रतिमाह करने को कहा गया है।
- साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि राशन कार्डधारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न का मैन्युअल वितरण न किया जाए।

स्कूल शिक्षा विभाग को मिला डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा-2022 अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

- 23 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक गतिविधियों को तकनीक के माध्यम से सहज बनाने के लिये राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग को एक वर्चुअल सम्मेलन में राष्ट्रीय इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा-2022 अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड एन.आई.सी. के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक ए.के. सोमशेखर द्वारा ग्रहण किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह अवार्ड स्कूली बच्चों के शैक्षणिक आकलन के लिये एनआईसी के सहयोग से विकसित एनक्लियर ऐप तथा टेली प्रेक्टिस ऐप के उपयोग के लिये दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे उक्त दोनों ऐप के माध्यम से स्कूली बच्चों की सहजता से आकलन एवं मॉनिटरिंग की जा सकती है।
- एनक्लियर में बच्चों को उनकी आईडी के साथ एक क्यूआर कोड कार्ड दिया जाता है, जिसका सालभर का 40 विद्यार्थियों पर व्यय मात्र 20 रुपए आता है। बच्चों को इस कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखना होता है।

- एनक्लियर ऐप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कक्षा में शिक्षकों द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्न पूछने पर बच्चों को सही उत्तर के आधार पर कार्ड को एक विशेष दिशा में पकड़कर प्रदर्शित करना होता है। शिक्षक द्वारा अपने मोबाइल कैमरे से कक्षा में एक जगह से सभी बच्चों के कार्ड को दूर से ही स्केन कर लिया जाता है। स्केन करते ही विद्यार्थियों का अपने आप आकलन हो जाता है और प्रश्नवार, विद्यार्थीवार रिपोर्ट शिक्षक एवं विभिन्न स्तरों पर देखी जा सकती है। इसमें शिक्षकों को प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को जाँचने एवं अंक देने के झंझट से मुक्ति मिलती है।
- इसी तरह विद्यार्थियों के आकलन के लिये एनआईसी द्वारा विकसित किये गए टेली-प्रेक्टिस ऐप के माध्यम से बच्चों के साथ मौखिक क्विज का आयोजन किया जा सकता है। इसके लिये टेलीग्राम ग्रुप में विद्यार्थियों को जोड़कर पायथोन नामक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को वाइस मैसेज भेजकर स्क्रीन पर चित्र एवं लिखित प्रश्न भेजा जाता है।
- इन प्रश्नों के मौखिक जवाब विद्यार्थियों द्वारा दिये जाते हैं। जिसे इस कार्यक्रम में एक साथ विद्यार्थियों के उत्तरों को एक फिल्म के रूप में व्यक्तिगत विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों एवं पालकों द्वारा देखा जा सकता है। शिक्षक विद्यार्थीवार वीडियो देखकर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के आधार पर अंक दे सकते हैं।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से एक साथ बहुत से विद्यार्थियों से सवाल करते हुए उनसे एक ही समय में उत्तर देने का प्रावधान होने से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों, दोनों का समय बचता है। शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी की स्थिति की जाँच करने में भी आसानी होती है और समय बचता है।
- इस प्रकार के आकलन के सप्रमाण होने से गलत आकलन की संभावनाओं से भी बचा जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को उनके उत्तरों के आधार पर उनका अपना वीडियो प्रश्न और उत्तर के साथ देखने का अवसर मिलता है। इन सबसे शिक्षकों का कार्य बहुत आसान हो जाता है।
- उल्लेखनीय है कि कोरोना संकटकाल के दौरान शिक्षा में नवाचार एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरे देश में अपनी एक पहचान कायम की है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना संकटकाल के दौरान स्कूली बच्चों को घर-बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने की तकनीक को देश ने सराहा है। 'पढ़ई तुंहर दुआर' को इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

छत्तीसगढ़ के अमनज्योति को मिलेगा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- 24 फरवरी, 2022 को भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली ने छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िला निवासी अमनज्योति जाहिरे का चयन राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 के लिये किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि साहसिक कार्यों और बहादुरी के लिये बच्चों को नगद राशि सहित प्रमाण-पत्र के साथ भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा हर साल यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- कोविड परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।
- अमनज्योति को उनके द्वारा किये गए साहसिक कार्यों के लिये हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
- कोरबा के रहने वाले 15 वर्षीय अमनज्योति ने एक अगस्त 2021 को फ्रेंडशिप डे के दिन अपने से उम्र में बड़े एक छात्र की जान बचाई थी।

डी.एन.बी. कोर्स के लिये मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बना दुर्ग ज़िला अस्पताल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DNB) द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िला अस्पताल को ई.एन.टी. (नाक, कान, गला) और पिडियाट्रिक (शिशु रोग) के लिये डी.एन.बी. कोर्स की मान्यता प्रदान की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही दुर्ग ज़िला अस्पताल डी.एन.बी. कोर्स के लिये मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है।
- डी.एन.बी. कोर्स की मान्यता प्राप्त होने के बाद अब हर साल ई.एन.टी. और पिडियाट्रिक की दो-दो सीटों पर पात्र चिकित्सक कोर्स पूर्ण कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे।
- दुर्ग ज़िला अस्पताल में डी.एन.बी. कोर्स की अनुमति जनवरी 2022 से दिसंबर 2026 तक के लिये दी गई है। इसके लिये अस्पताल में कार्यरत ई.एन.टी. एवं पिडियाट्रिक विभाग के चिकित्सकों को फैकल्टी निर्धारित किया गया है। डी.एन.बी. दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम है।

मुख्यमंत्री ने तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

- 25 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य करमा की रंगारंग प्रस्तुति के बीच प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में 107 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- बिलासपुर-रायपुर रोड स्थित तिफरा में नए फ्लाईओवर ब्रिज के बन जाने से महाराणा प्रताप चौक और तिफरा छोर में जाम से मुक्ति मिल जाएगी। रायपुर मार्ग को बिलासपुर शहर से जोड़ने वाले इस ब्रिज से शहरवासियों के साथ-साथ उन तमाम राहगीरों को भी राहत मिलेगी, जो एन.एच. 130 का उपयोग आवागमन के लिये करते हैं।
- तिफरा छोर से स्वर्गीय जमुना प्रसाद वर्मा कॉलेज तक 1620 मीटर की लंबाई में तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया गया है।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बिलासपुर को व्यापार विहार स्मार्ट रोड और प्लेनेटोरियम की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के लालबहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर शहर और बिलासपुर ज़िले के लिये लगभग 353 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत के 97 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया।
- बिलासपुर शहर में महाराणा प्रताप चौक से तारबाहर चौक तक बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगभग 26 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से व्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्मार्ट रोड का निर्माण किया गया है।
- संभाग के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र होने की वजह से इस मार्ग में भारी वाहनों का आवागमन हमेशा लगा रहता है, लेकिन पूर्व में इस मार्ग के अव्यवस्थित होने की वजह से हमेशा ट्रैफिक और जाम की समस्या बनी रहती थी। फोरलेन स्मार्ट रोड बन जाने से व्यापार विहार में व्यापारिक परिवहन सहज और सुगम होगा।
- बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा साढ़े तीन एकड़ में 6 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम का निर्माण किया गया है। इस प्लेनेटोरियम में शहरवासियों को दिन में ही आकाशीय नज़ारे के अवलोकन के साथ-साथ विज्ञान तथा खगोलशास्त्र के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।
- दो सौ लोगों की बैठक क्षमता वाले इस प्लेनेटोरियम में आगंतुकों के लिये फोर के सिंगल टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्टर लगाया गया है, इसके अलावा प्लेनेटोरियम परिसर में ऑक्सीजोन का भी निर्माण किया गया है। प्लेनेटोरियम पहुँचने वाले आगंतु को की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पहुँच मार्ग का भी निर्माण किया गया है।

अब छत्तीसगढ़ में कृषि में गोमूत्र का होगा वैज्ञानिक उपयोग

चर्चा में क्यों?

- 25 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के मुख्य सचिव को ऑर्गेनिक एवं रिजेनरेटिव खेती की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में गोमूत्र के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उपयोग की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कृषि वैज्ञानिकों, गोमूत्र का रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बदले उपयोग करने वाले कृषकों तथा कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से चर्चा कर गोमूत्र के वैज्ञानिक उपयोग की संभावनाओं के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर दो सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा है।
- राज्य में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का खेती में बड़े पैमाने पर उपयोग एवं इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए गोमूत्र को रासायनिक खादों एवं विषैले कीटनाशकों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक खादों एवं विषैले कीटनाशकों के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की उर्वराशक्ति निरंतर कम होती जा रही है। खेती में रसायनों के अत्यधिक उपयोग से जन-सामान्य के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। राज्य के गोठानों में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट का उपयोग आरंभ करने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक एवं रिजेनरेटिव खेती की ओर आगे बढ़ रहा है।
- इसी तरह कृषि में ज़हरीले रसायनों के उपयोग के विकल्प के रूप में 'गोमूत्र'के उपयोग की अपार संभावनाएँ हैं। राज्य के ही कुछ स्थानों में गोमूत्र के सफलतापूर्वक उपयोग के उदाहरण मौजूद हैं।
- उन्होंने कहा कि गोमूत्र के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के पूर्व इस दिशा में अब तक देश में हुए शोध का संकलन भी किया जाना चाहिये।

छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग का आईसीसीआर के साथ एमओयू

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के साथ एमओयू किया है। एमओयू के बाद अब देश और दुनिया में होने वाले कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी कलाकारों को भी प्रस्तुति का मौका दिया जाएगा, जो देश और दुनिया के साथ राज्य का सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण होगा।

प्रमुख बिंदु

- इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस संस्था भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का उपक्रम है। ये संस्था विश्व स्तर पर भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये काम करती है। इसके तहत विश्व के अन्य देशों में कला, संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम कराए जाते हैं।
- छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने बताया कि विदेश से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिये कोई भी जानकारी अब राज्य को भी सूचित की जाएगी।
- संस्कृति विभाग द्वारा राज्य के कलाकारों को प्रस्तुति के लिये भेजा जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को विदेश में प्रस्तुति देने का महत्त्वपूर्ण मौका मिलेगा, साथ ही हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया देख सकेगी। इसके माध्यम से राज्य के कलाकारों को विदेशी कल्चर जानने का भी अवसर मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में अब तक राज्य के 2 हज़ार 25 कलाकार और 443 कला दल रजिस्टर्ड हैं।

गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 27 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने यूनियन क्लब रायपुर में मध्य भारत के प्रतिष्ठित गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- शुभारंभ समारोह में राज्यपाल उइके द्वारा राज्य के उभरते हुए उत्कृष्ट टेनिस खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा इस अवसर पर राज्यपाल उइके को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
- राज्यपाल ने गोंडवाना कप का शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों से कहा कि वे खेल भावना से खेलें और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के साथ अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। खेल जीवन में अनुशासन सिखाता है और नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। खेल से राष्ट्रीयता और देश-प्रेम की भावना भी बढ़ती है।
- उल्लेखनीय है कि गोंडवाना कप की शुरुआत लगभग 85 वर्ष पहले 1937-38 में हुई थी और यूनियन क्लब, रायपुर ही गोंडवाना कप का सर्वप्रथम आयोजक रहा।
- छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ ने एक और उल्लेखनीय कार्य करते हुए पिछले साल से गोंडवाना कप आईटीएफ वुमेंस टेनिस स्पर्द्धा की शुरुआत की है।

दृष्टि The Vision